12,209 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश

उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र को रफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के विकास को रफ्तार, ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा और युवाओं को कौशल विकास व रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने इस वर्ष का पहला 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा के पटल पर रखा।

बजट का दो तिहाई हिस्सा गंगा एक्सप्रेसवे, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। अनुपूरक बजट में 7500.81 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास और 2000 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे वे को महाकुंभ से पहले तैयार करने के लक्ष्य के तहत कुल बजट का लगभग आधा हिस्सा 6400 करोड़ रुपये गंगा एक्सप्रेसवे को दिया गया।

अनुपूरक बजट में राजस्व लेखा व्यय 4, 227.94 करोड़ और पूंजी लेखा का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। इससे पहले फरवरी में वित्त मंत्री ने 7.37 लाख करोड़ रुपये का पूर्ण बजट पेश किया था। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट था।

अनुपूरक बजट में 1000 करोड़ रुपये परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए प्रस्तावित किया है। यूपी कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

अनुपूरक बजट में किसे मिली कितनी रकम

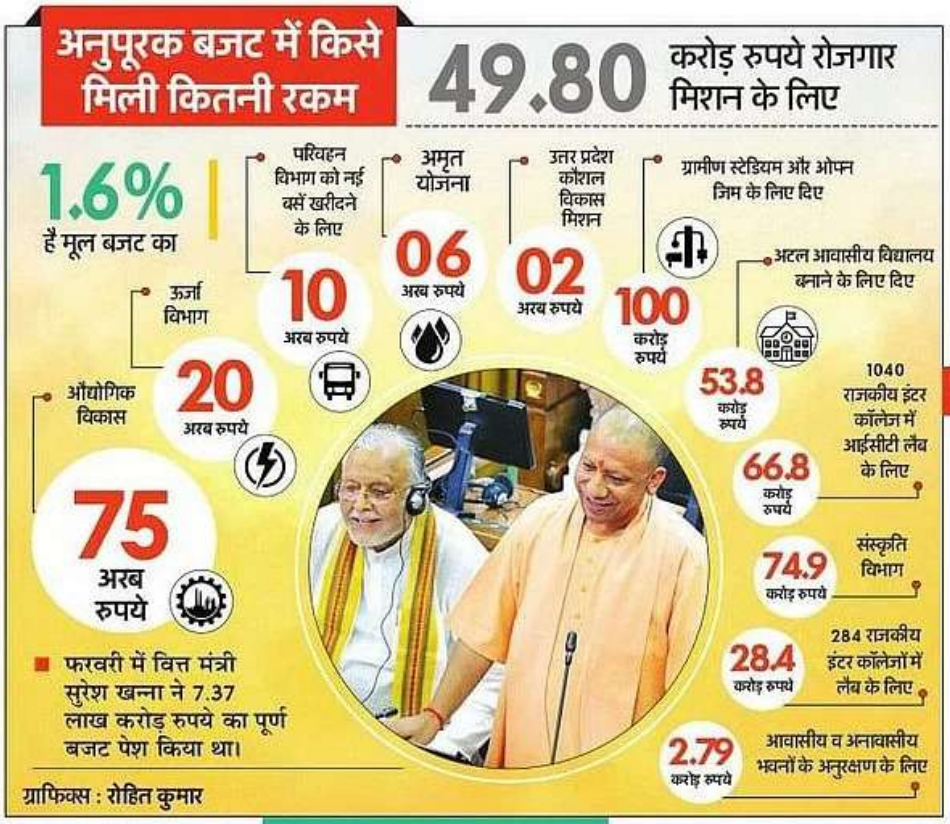

ग्राफिक्स : रोहित कुमार

महाकुंभ पर भी फोकस

6400 करोड़ रुपये का गंगा एक्सप्रेसवे के लिए प्रावधान किया गया

7,981.99 करोड़ रुपये पूंजी लेखा व्यय

- राजस्व लेखा व्यय 4 हजार 227.94 करोड़ रुपये
- 3.25 करोड़ विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण के लिए

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

युवाओं को राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्यूनिकेशन सिस्टम और सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना के लिए 2.45 करोड़ दिए हैं। वहीं अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। - **सुरेश कुमार खन्ना, वित्त मंत्री**

>> उद्योगों को सब्सिडी में 1200 करोड़ : पेज 5

अनुपूरक बजट क्यों

अनुपूरक बजट ऐसा वित्तीय दस्तावेज है, जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस स्थिति में पेश करती है, जब उसे पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है, जिनको फरवरी में पेश पूर्ण बजट में शामिल नहीं किया गया था, या जो नई परिस्थितियों के कारण जरूरी हो गए हों। यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है।

अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में बढ़ेंगी सुविधाएं

लखनऊ। सरकार ने अनुपूरक बजट में शहरी विकास के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें 50 करोड़ रुपये अयोध्या, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं को और बेहतर करने पर खर्च किया जाएगा जबकि शेष 600 करोड़ रुपये अमृत योजना के तहत कराए जा रहे सीवरेज और पेयजल की परियोजनाओं पर खर्च होंगे।

- अयोध्या में श्रीराम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। यही स्थिति मथुरा में भी है। इसको देखते हुए इन तीनों धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विकास हो रहा है। इसलिए अनुपूरक बजट में इन तीनों स्थानों के लिए अलग से राशि की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो